an>

Title: Regarding problems faced by the farmers due to weak monsoon in the country.

श्री जगदम्बिका पाल(डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न को आपके समक्ष रख रहा हूं और कदाचित यह पूरे सम्मानित सदन से जुड़ा हुआ विषय है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं हैं, पूरे देश में जो एक सामान्य वर्षा होनी चाहिए, वह 195.7 मिलीमीटर नार्मल जून के महीने में है, एक जून से दो जुलाई तक देश के हिस्सों में अगर सामान्य बारिश होती है तो वह 195.7 मिलीमीटर होती है। लेकिन वास्तविक रूप से जून में 195.7 के सापेक्ष केवल 109 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह रिपोर्ट हमारी नहीं है, यह इंडियन मिटिरियोलोजिकल डिपार्टमैन्ट की रिपोर्ट है कि जून महीने में सामान्य से 42 प्रतिशत बारिश कम हुई है। स्वाभाविक है कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे तो कहेंगे कि मान लिया फसल प्रभावित होगी, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण क्षमता है और अन्न की कोई कमी नहीं है। मैं यह मान लेता हूं कि देश के राज्यों की आवश्यकता के अनुसार आप पीडीएस में केन्द्रीय पूल से अन्न दे देंगे, लेकिन जो खरीफ की फसल है, जो किसान पहली जुलाई से सोइंग करता है, धान की बुआई करता है या धान को बैठाता है या दलहन या तिलहन की जब पैदावार कम होगी, वह पैदावार जिसकी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि साफ तौर से पिछले साल 2013-14 में 264 मीट्रिक टन पैदावार हुई थी। इस बार संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, वह 261 मीट्रिक टन है। यह जो सैन्टर फार मानिटरिंग इंडिया इकोनोंमी है, उसके हिसाब से भी जो मानिटरिंग हुई है, वह .06 परसैन्ट कम पैदावार होने की संभावना है, तो निश्चित तौर से इस बात को जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी आर्थिक सर्वेक्षण रख रहे थे, उस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में भी कहा गया कि एक तरफ इराक के संकट को लेकर और दूसरी तरफ इस देश के कम मानसून को लेकर हमारे जीडीपी पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसे सरकार भी स्वीकार कर रही है कि कम मानसून के कारण न केवल पैदावार को नुकसान होगा, बल्कि हमारी कृषि की विकास दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी।

महोदय, एक तरफ केन्द्र सरकार का बजट आया है, वह निश्चित तौर से गतिशील बजट है, देश की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट है और सभी ने उसका स्वागत किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रकृति का पक्ष है, उस प्रकृति के कारण सभी राज्यों के लिए एक कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह बात जब एक सचाई है कि 42 परसैन्ट औसत हुआ है और कुछ राज्यों में उससे ज्यादा है। यहां तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यो में जहां 10 से 15 जून के बीच में मानसून आता था, वहां के आईएमडी के आंकड़े हैं कि 91 फीसदी कम बारिश हुई है। अगर मैं राज्यवार कहूं तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, मैं इसमें सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप देखते हैं, आप स्वयं विद्वान हैं कि अवर्षण होने से कई संकट पैदा हो जाते हैं। गांवों के तालाब सूख जाते हैं, जल स्तर नीचे चला जाता है तो उसके कारण व्यक्तियों से ज्यादा जानवरों के लिए संकट पैदा हो जाता है। मैं समझता हूं कि उन जिलों के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए और ताल, तालाब, तलैयों को भरवाया जाए। आज आपने सुबह रिपोर्ट देखी होगी कि मुम्बई हो या दिल्ली हो, यहां भी पेयजल का संकट पैदा हो रहा है। पानी की कटौती अगर इन मैट्रो सिटीज में हो रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं देश के दूसरे राज्यों और सुदूर अंचलों में क्या हो रहा है। इसी तरीके से पशुओं के बारे का संकट है। सिंचाई के लिए स्वाभाविक है कि मैं कहूंगा कि अतिरिक्त बिजली दी जानी चाहिए। मैं इस विषय पर यहां नहीं खड़ा हूं कि राज्य यह खड़े होकर कहें कि केन्द्र से दिला दीजिए। लेकिन इसका कोई न कोई समन्वय स्थापित हो। इस समय किसानों को मानसून की कमी के कारण जो धान की बुआई करने के लिए, खेत को भरने के लिए जब तक ट्यूबवैल नहीं चलेंगे, तब तक निश्चित तौर पर किसान का जो क्षेत्रफल है, वह पूरा सिंचित नहीं होगा। इसमें अतिरिक्त बिजली मिलनी चाहिए। पेयजल के लिए जिलेवार कोई एक कार्य योजना बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के लिए एक समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसलिए जो अवर्षण से, सूखे से जो एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है, इसके संबंध मैं मांग करता हूं कि इस पर केन्द्र सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब आ जाए या इस पर सरकार कुछ रिस्पांड कर दे तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। क्योंकि यह विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है।

माननीय सभापति :

श्री पी.पी.चौधरी अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल के विषय से सम्बद्ध करते हैं।